भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6297

02 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुई प्रगति

6297. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री विष्णु दयाल रामः

श्री रमेश अवस्थीः

श्री तेजस् वी सूर्याः

श्री दुलू महतोः

श्री बलभद्र माझीः

श्रीमती कमलजीत सहरावतः

श्री योगेन्द्र चांदोलियाः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

श्री प्रवीण पटेलः

श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत विशेषकर नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित देशभर में शहरी गतिशीलता, एकीकृत कमान और नियंत्रण केन्द्रों, जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में हुई प्रगति का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देशभर के अन्य नगरीय स्थानीय निकायों और शहरों में नगरीय शासन और सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के लिए एससीएम के अंतर्गत विकसित सर्वोत्तम पद्धतियों और प्रौद्योगिकी समाधानों को दोहराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) नीति आयोग ने सितंबर 2025 में प्रकाशित 'पैकेज 4 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन - शहरी परिवर्तन और कौशल विकास' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि स्मार्ट सिटी मिशन राष्ट्रीय शहरी प्राथमिकताओं और नागरिक

जरूरतों के साथ मजबूत संरेखण प्रदर्शित करता है, जिसने संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, मिशन ने 8,063 परियोजनाओं में 93% की उच्च परियोजना पूर्णता दर और एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) को 100% पूरा करने की उच्च दर हासिल की है, जिससे शहरी जीवन, गतिशीलता, सुरक्षा और पर्यावरणीय परिणामों में मापन योग्य सुधार हुआ है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने दो चक्रों में आईसीसीसी मैच्योरिटी एसेसमेंट फ्रेमवर्क (आईएमएएफ 2.0) के तहत एक व्यापक स्व-मूल्यांकन किया है। आईएमएएफ 2.0 एक संरचित स्व-मूल्यांकन टूल के रूप में कार्य करता है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर, उपयोग के मामलों, साइबर सुरक्षा, डेटा लाइफ सायकल प्रबंधन, शासन टीम प्रबंधन, व्यवसाय योजना, अंतर-विभागीय समन्वय, हितधारक सहभागिता और बढ़ी हुई दक्षता और प्रभाव के लिए मध्य पाठ्यक्रम सुधार को संभव करने के लिए नवाचार को अपनाने जैसे दस परिभाषित स्तंभों में आईसीसीसी की मैच्योरिटी का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मूल्यांकन के परिणामों को सभी 100 स्मार्ट शहरों के साथ व्यक्तिगत रूप से साझा किया गया था ताकि उन्हें कमियों को समझने और अपने आईसीसीसी संचालन में सुधार करने में मदद मिल सके।

(ख) स्मार्ट सिटी मिशन के दौरान केन्द्र सरकार की प्रमुख भूमिकाओं में से एक लाइट हाउस के रूप में अद्वितीय प्रायोगिक परियोजनाओं को विकसित करने, उनका प्रलेखन करने में शहरों को सहायता देना रहा है ताकि उन्हें अन्य शहरों में कार्यान्वित किया जा सके। ये सभी दस्तावेज मंत्रालय के पोर्टल पर सार्वजनिक डोमेन पर हैं। मंत्रालय ने 'मेकिंग सिटी स्मार्ट' नामक सौ शहरों के अनुभवों से सीखते हुए दस्तावेज भी तैयार किया है, जिसे सभी राज्यों को भेजा गया है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इसे अपने-अपने राज्यों के अन्य शहरों में संदर्भ दस्तावेज के रूप में उपयोग करें।

*****